आत्मनिर्भर भारत के लिए नैतिक धन सृजन

डॉ कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन
सुरभि जैन

''गंगा के मैदान में उगे गेहूं से, कावेरी नदी-क्षेत्रों में खिलते पान का, करेंगे वस्तु विनिमय।
सिंह समान शौर्य युक्त मराठियों की कविता लेकर, देंगे (हम) केरल के हस्ति-दंत।।''
– सुब्रह्मण्य भारती

आत्मनिर्भर भारत के सपने संजोते हुए राष्ट्रवादी महाकवि सुब्रह्मण्य भारती ने उपरोक्त उद्‌गार व्यक्त किए थे। भारत को अब आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनना ही होगा। कोविड-19 महामारी के संकट के दौर में इस जरूरत को स्पष्ट रूप से उभारा है, जिसमें दुनियाभर में अर्थव्यवस्था की कई कमियां उजागर हुई हैं।

आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर नागरिक

किसी भी देश में धन का सृजन लोगों की इच्छाशक्ति और सृजनात्मकता पर निर्भर करता है। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण देश के आत्मनिर्भर लोगों द्वारा ही किया जा सकता है। भारत 130 करोड़ लोगों का परिवार है। देश का हर परिवार का एक सदस्य भी अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण में अगर थोड़ा-थोड़ा योगदान करता है, तो हमारी आबादी को सामूहिक ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग अपनी पूरी क्षमता पर भरोसा करके पूरी ऊर्जा लगाकर काम करेंगे, वे बड़ा से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। अगर किसी के पास कौशल है और वह अपनी आजीविका के लिए कमाई कर सकता/सकती है, वह आत्मनिर्भर हो जाता/जाती है। कौशल विकास के लिए अवसर प्रदान कर सरकार इस प्रक्रिया को तेज कर सकती है। देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार और नागरिकों के बीच सामाजिक तालमेल ऐसा होना चाहिए, ''जहां सरकार सक्रियतापूर्वक निजी जिम्मेदारी पूरी करने में लोगों की मदद करे, न कि निजी जिम्मेदारी के बदले या सामुदायिक जिम्मेदारी के सिलसिले में सरकारी सहायता मुहैया कराई जाए।'' अगर आत्मनिर्भर नागरिकों के लिए सक्रिय सरकारी सहायता मुहैया कराना है, तो उनकी प्रेरणा और आत्म-सम्मान को बनाए रखना होगा। लिहाजा, सब्सिडी या अनुदान (खास तौर पर वह अनुदान जिसके लाभार्थी अपेक्षाकृत संपन्न लोग हैं) को आत्मनिर्भर भारत के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता।

अनुदान पर होने वाले खर्च का इस्तेमाल शिक्षा और देश के नागरिकों के कौशल/संसाधन विकास में किया जाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए अर्थव्यवस्था को आधुनिक तकनीक से लैस करना होगा और बड़े पैमाने पर युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मुहैया कराना होगा।

रोज़गार से समावेशी विकास

आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब देश के हर नागरिक के लिए आत्मनिर्भरता है। लिहाजा, आत्मनिर्भरता से जुड़ी विकास की रणनीति का सबसे अहम मकसद समावेशी विकास है। कुछ देशों में बड़े स्तर पर मौजूद असमानताओं के अनुभव से कहा जा सकता है कि जीडीपी वृद्धि दर आर्थिक विकास का एकमात्र मकसद नहीं हो सकती।

अर्थशास्त्र के 'ट्रिकल डाउन' सिद्धांत के मुताबिक, अगर जीडीपी में बढ़ोतरी होती है, तो जरूरी नहीं है कि सभी (या ज्यादातर) लोगों की आय उसी हिसाब से बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर, कई देशों और क्षेत्रों में सामान्य (बिना कौशल वाले) मजदूरों की आय स्थिर हो गई है, जबकि क्षेत्र (देश) की जीडीपी में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। आर्थिक विकास का यह असमान ढांचा आत्मनिर्भर भारत के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सिर्फ वैसी आर्थिक नीतियों के जरिये हासिल किया जा सकता है, जिसमें विकास के अलावा आर्थिक असमानता को भी कम किया जा सके। समानता और विकास को एक-दूसरे की कीमत पर हासिल करना ठीक नहीं होगा। समानता और विकास को एक-दूसरे का पूरक होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी आर्थिक रणनीति में बड़े बदलाव करने होंगे, ताकि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

डॉ कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ईमेल: cea@nic.in
सुरभि जैन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक हैं। ईमेल: surbhi.jain@nic.in

रोज़गार सृजन समावेशी विकास के लिए सबसे अहम है। जब किसी परिवार के एक व्यक्ति को संगठित क्षेत्र में रोज़गार मिलता है, तो पूरे परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाती है। इसके अलावा, परिवार के एक सदस्य को संगठित क्षेत्र में रोज़गार मिलने पर उसके बच्चों का भी भविष्य बेहतर होने की संभावना रहती है। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। अगर श्रम-शक्ति के एक बड़े हिस्से का उपयोग नहीं होता है या आंशिक उपयोग होता है, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए बेहद नुकसानदेह है। दरअसल, इससे उत्पादन में श्रम-शक्ति की क्षमता का पूरा-पूरा तरह इस्तेमाल नहीं हो पाता है।

रोज़गार सृजन समावेशी विकास के लिए सबसे अहम है। जब किसी परिवार के एक व्यक्ति को संगठित क्षेत्र में रोज़गार मिलता है, तो पूरे परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाती है। इसके अलावा, परिवार के एक सदस्य को संगठित क्षेत्र में रोज़गार मिलने पर उसके बच्चों का भी भविष्य बेहतर होने की संभावना रहती है। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

शुभ लाभ से ऋद्धि और सिद्धि

आत्मनिर्भरता का मतलब निजी क्षेत्र और सरकार की पूरक भूमिकाओं की पहचान करना है। दरअसल, बाजार की ताकतों की पहचान किए बिना आत्मनिर्भरता को हासिल नहीं किया जा सकता और सामान्य परिस्थितियों में निजी उद्यम हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बाजार की ताकतें कीमतों और लाभ के आधार पर संसाधनों का आवंटन करती हैं, लिहाजा वे सामान्य परिस्थितियों में आर्थिक बेहतरी को बढ़ावा देती हैं। इस तरह, निजी उद्यम को बढ़ावा देना आत्मनिर्भरता का एक अहम पहलू है। 'शुभ-लाभ' की अवधारणा का मतलब यह है कि लाभ बुरी चीज नहीं है। यह इंसान के प्रयासों के लिए प्रेरणास्रोत है और सामाजिक समृद्धि और कारोबार-लाभ को एक-दूसर से अलग कर नहीं देखा जा सकता। अत: आत्मनिर्भरता का मतलब 'लाइसेंस परिमट राज' की वापसी नहीं है और न ही इससे यह आशय है कि सरकार फिर से तमाम चीजों को नियंत्रित करने लगेगी। दरअसल, भारतीय कारोबारों में हमेशा ऋद्धि (धन और समृद्धि) और सिद्धि (कौशल) को एक साथ स्थान दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि विशेषज्ञता और सफलता को अलग नहीं किया जा सकता। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार को इस तरह से ऋद्धि और सिद्धि को बढ़ाना चाहिए:

1. हमारे नागरिक कौशल सीखें (सिद्धि)।
2. हमें मझोले और छोटे उद्योगों की सहायता के लिए उन्हें तकनीक से लैस श्रम मुहैया कराना चाहिए। मजदूरों की सिद्धि इन उद्योगों और मजदूरों, दोनों के लिए धन का सृजन करेगी।
3. हमें शोध और विकास एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था, मेडिकल शोध जैसे नवाचार में निवेश करना चाहिए: सिद्धि
4. हमें पृथ्वी के संसाधनों का सार्थक इस्तेमाल करते हुए तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयास करना चाहिए (सिद्धि)।
5. हमें ऋद्धि और सिद्धि, दोनों के जरिये बाकी दुनिया की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए।

साथ ही, जैसा कि मौजूदा कोरोना संकट के दौरान देखने को मिला है, बाजार की ताकतें और निजी उद्यम आपदा और युद्ध जैसी स्थितियों के दौरान सुस्त या पूरी तरह ठप्प हो सकती हैं। अगर बाजार और निजी उद्यम समाज की सभी जरूरतों को पूरा कर पाते, तो मास्क, सैनेटाइजर या सुरक्षा उपकरण की कमी नहीं होती। इन चीजों की बढ़ी मांग पूरी हो जाती और किल्लत नहीं होती। हालांकि, इन चीजों की भारी किल्लत हमें ऐसे आर्थिक मॉडल को अपनाने की तरफ इशारा करती है जिसमें आत्मनिर्भरता के लिए गुंजाइश हो। इस वजह से स्वास्थ्य, जीवन-रक्षक दवाओं, भुगतान प्रणाली, मोबाइल संचार और रक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में सरकार को अपनी आर्थिक मौजूदगी रखनी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की एक या दो फर्मों

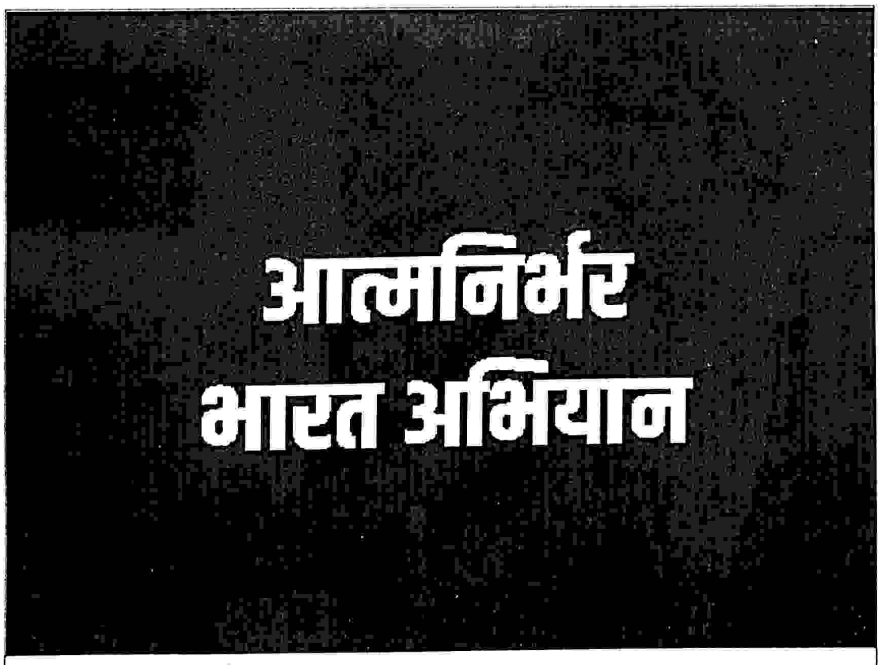

एक आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने आह्वान में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकास को बनाए रखने के लिए पांच स्तंभों पर जोर दिया: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली (आधुनिक तकनीक पर आधारित) जीवंत जनसांख्यिकी और मांग।

के जरिये ऐसा किया जा सकता है। व्यापक अर्थों में आत्मनिर्भरता से आशय यह है कि सरकार को अहम क्षेत्रों की पहचान कर उनमें विनिर्माण की क्षमता सुनिश्चित करनी चाहिए।

आम तौर पर विकास में सरकार की भूमिका को प्रभावी नहीं माना जाता है। हालांकि, भारत के हाल के अनुभव इस तरह की चिंताओं को खारिज करते हैं। उदाहरण के तौर पर, गरीब लोगों के बैंक खाते में अनुदान या अन्य तरह की मदद पहुंचाने में जन धन योजना काफी मददगार हो रही है। इसी तरह, स्वच्छ भारत अभियान साफ-सफाई को लेकर जागरूकता फैलाने में काफी सफल रहा है और इसका स्वास्थ्य के मोर्चे पर सकारात्मक असर देखने को मिला है। इन दोनों कार्यक्रमों के जरिये जो नतीजे हासिल हुए, वे निजी उद्यम के जरिये संभव नहीं थे। इससे साफ पता चलता है कि समय के साथ हमने असफलता का जोखिम कम करने और सरकारी कार्यक्रमों में सफलता की संभावना बढ़ाने के बारे में सीखा है। बहरहाल, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सरकार की भूमिका अहम है। लिहाजा हमारी कोशिश सरकार की दक्षता और क्षमता बढ़ाने को लेकर होनी चाहिए।

सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोगों के लिए उत्पादन

आत्मनिर्भरता का मतलब यह है कि भारतीय कंपनियां ऐसे सामान और सेवाओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे हमारी बड़ी आबादी की जरूरतें पूरी हो सकें। वरिष्ठ अकादमिक सी के प्रह्लाद का कहना है कि आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोग धन का अहम जरिया हो सकते हैं। हालांकि, इस धन को कमाने के लिए उत्पाद को ग्राहकों की जेब के हिसाब से तैयार करना होगा। सैशे क्रांति यानि छोटे सैशे (पैकेट) में शैंपू, टूथपेस्ट या तेल की पैकेजिंग से गरीब तबके के लोग भी आसानी से इन उत्पादों की खरीद कर सकते हैं- यह इस फॉर्मूले का एक बेहतरीन उदाहरण है। गरीबों के पास बड़ी मात्रा में इन उत्पादों को खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। हालांकि, अमीरों की तरह वे भी उन उपभोक्ता सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अत: आत्मनिर्भर भारत के लिए विकास की रणनीति पर अमल करने से छोटे और मध्यम उद्यमों को वैसे सामान और

भारत के आर्थिक बदलाव के लिए कृषि महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने से खाद्य सुरक्षा और भुगतान संतुलन (खाद्यान्नों के आयात में कमी और निर्यात में बढ़ोतरी) की स्थिति बेहतर होगी। साथ ही, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा, कृषि आधारित उद्योगों के लिए गुंजाइश बढ़ेगी और खेती से जुड़ी कई अन्य सेवाओं की मांग बढ़ेगी। इस तरह, रोज़गार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ आय में भी बढ़ोतरी होगी। कृषि से जुड़ी सामग्री का निर्यात बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। इसके लिए ऊंचे मूल्य वाले ऐसी फसलों की पहचान करनी होगी, जिसकी मांग भारत के बाहर भी है। इसके अलावा, कृषि की व्यवस्था को तकनीकी तौर पर भी काफी उन्नत बनाया जा सकता है और इससे जुड़े कुछ कौशल का उपयोग दूसरे क्षेत्रों में किया जा सकता है।

सेवाओं का उत्पादन करने में मदद मिलेगी, जो गरीबों की पहुंच के दायरे में भी हो। भारतीय कंपनियां गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कारोबारी मॉडल अपनाती हैं, उसके जरिये वे एशिया और अफ्रीका के कई विकासशील बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ा सकती हैं। अत: गरीब उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने वाले विकास मॉडल की मदद से आत्मनिर्भर भारत न सिर्फ दूसरों की मदद कर सकेगा, बल्कि वैश्विक आर्थिक ताकत के तौर पर अपनी जगह भी बनाने में सफल होगा।

आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि का महत्व

भारत के आर्थिक बदलाव के लिए कृषि महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने से खाद्य सुरक्षा और भुगतान संतुलन (खाद्यान्नों के आयात में कमी और निर्यात में बढ़ोतरी) की स्थिति बेहतर होगी। साथ ही, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा, कृषि आधारित उद्योगों के लिए गुंजाइश बढ़ेगी और खेती से जुड़ी कई अन्य सेवाओं की मांग बढ़ेगी। इस तरह, रोज़गार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ आय में भी बढ़ोतरी होगी। कृषि से जुड़ी सामग्री का निर्यात बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। इसके लिए ऊंचे मूल्य वाले ऐसी फसलों की पहचान करनी होगी, जिसकी मांग भारत के बाहर भी है। इसके अलावा, कृषि की व्यवस्था को तकनीकी तौर पर भी काफी उन्नत बनाया जा सकता है और इससे जुड़े कुछ कौशल का उपयोग दूसरे क्षेत्रों में किया जा सकता है। दरअसल, कृषि में नवाचार के पर्याप्त मौके हैं- जैसे कि फसलों का बेहतर मिला-जुला रूप, बेहतर खाद, बेहतर बीज, बुआई का बेहतर तरीका। खेती को पारंपरिक तरीकों से बदलकर आधुनिक तकनीक से जोड़ने से कुछ स्तरों पर समाज में भी बदलाव और आधुनिकीकरण की राह आसान हो सकती है।

कृषि के क्षेत्र में बेहतर बदलाव से शहरों में पलायन की समस्या और इससे उपजी चुनौतियों को भी कम करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, घर समेत शहरी आधारभूत संरचना के लिए दुर्लभ संसाधनों का इस्तेमाल को भी कम किया जा सकता है। शहरों में विनिर्माण के क्षेत्र में रोज़गार सृजन की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए ज्यादा पलायन समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसके अलावा, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी से आय में बढ़ोतरी होगी, जिसका लाभ कई स्तरों पर दिखेगा और कुल मांग में बढ़ोतरी के लिए गुंजाइश बनेगी।

नैतिक धन सृजन

जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के अस्तित्व के लिए चुनौतियां पैदा हो गई हैं। लिहाजा, विकास के लिए रणनीति बनाते समय हमें पर्यावरण के पहलू को ध्यान में रखना होगा। कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान हमें यह भी पता चला कि काफी बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां किस तरह से हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल असर डालती हैं। लॉकडाउन के दौरान गंगा नदी में फैक्ट्रियों का कचरा गिरना बंद हो जाने के कारण पानी की शुद्धता का स्तर काफी बढ़ गया। साथ ही, पंजाब से हिमालय का नज़ारा दिखने लगा-पिछले पांच दशक में ऐसा संभव नहीं था।

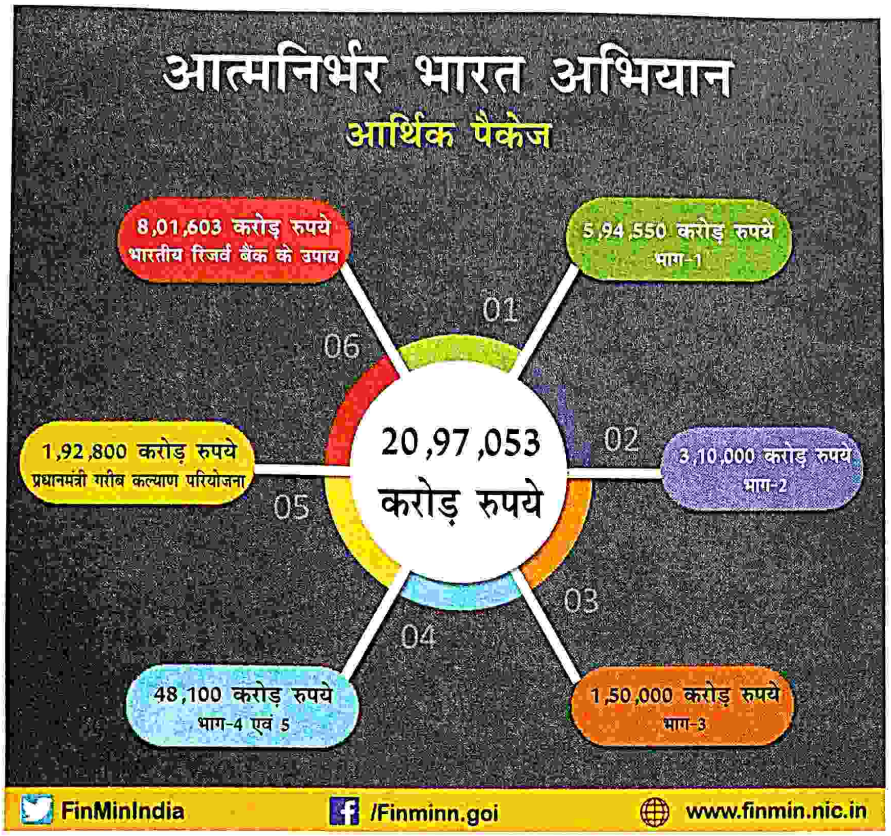

ऐतिहासिक तौर पर भी भारत लंबे समय तक दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत रहा है। एंगस मैडिसन के शोध के मुताबिक, 1750 ईस्वी तक दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भारत की हिस्सेदारी एक तिहाई से भी ज्यादा थी। भारत का लंबी अवधि तक दुनिया की प्रमुख आर्थिक ताकत के रूप में बने रहना इस बात का सबूत है कि यह महज संयोग नहीं था। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में भी बताया गया है कि भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक दबदबा इसलिए रहा है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में नैतिक रूप से धन कमाने को एक बेहतर मानवीय लक्ष्य माना जाता था। उदाहरण के लिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र अर्थोपार्जन पर ग्रंथ है। भारतीय साहित्य से जुड़े बाकी ग्रंथों में भी धन सृजन को योग्य मानवीय लक्ष्य बताया गया है। तमिल संत और दार्शनिक तिरुवल्लुवर ने अपनी पुस्तक 'तिरुक्कुरल' के 76वें अध्याय के 753वें पद में लिखा है, "धन का प्रकाश हर जमीन को रोशन करता है। यह ईश्वर के आदेश पर अंधेरा दूर भगाता है।" प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में धन सृजन के साधनों पर उतना ही जोर दिया गया है। 'तिरुक्कुरल' के 754वें पद में कहा गया है, "अगर किसी को नुकसान पहुंचाए बिना धन हासिल किया जाता है, तो यह खुशी और सकारात्मकता प्रदान करता है।" भारतीय परंपरा में आध्यात्मिक, नैतिक और दार्शनिक आयामों को शामिल करते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि निजी लोभ सामाजिक स्तर पर बर्बादी का कारण नहीं बने।

आर्थिक विकास, पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए बिना हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संस्कृति मे नैतिक धन सृजन की वकालत की गई है। अब इसे विकास का वैश्विक मॉडल बनाने की जरूरत है। इसके लिए भारत को पहल कर घरेलू स्तर पर उदाहरण पेश करने की भी दरकार है। भारत को खास तौर पर 'मितव्ययी नवाचार' के लिए पहल करनी होगी, ताकि हम बड़े पैमाने पर मानवता के कल्याण के लिए 'धरती माता' के संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल कर सकें।

आर्थिक विकास, पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए बिना हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संस्कृति मे नैतिक धन सृजन की वकालत की गई है। अब इसे विकास का वैश्विक मॉडल बनाने की जरूरत है। इसके लिए भारत को पहल कर घरेलू स्तर पर उदाहरण पेश करने की भी दरकार है। भारत को खास तौर पर 'मितव्ययी नवाचार' के लिए पहल करनी होगी, ताकि हम बड़े पैमाने पर मानवता के कल्याण के लिए 'धरती माता' के संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल कर सकें। भारत को इस मामले में अगुवाई करते हुए पूरी दुनिया को 'मितव्ययी नवाचार' की अहमियत बताना चाहिए।

आत्मनिर्भरता का अर्थ सब कुछ खुद से करना नहीं

आत्मनिर्भरता का मतलब सब कुछ खुद से करना नहीं होता। व्यक्ति या देश, दोनों मामलों में यह बात लागू होती है। इसी तरह, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने का यह मतलब भी नहीं है कि उसका अन्य जगहों से जुड़ाव न हो। आत्मनिर्भरता से आशय यह समझना है कि जब हम मदद के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो कई बार ऐसा होगा जब आपको मदद नहीं मिल सकती। कई बार जब हम मदद के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो हमारी स्थिति काफी नाजुक होती है। आत्मनिर्भरता का मतलब बेहद नाजुक स्थिति में भी अपने लिए आत्मनिर्भर होने की क्षमता से लैस होना है। लिहाजा, आत्मनिर्भरता का मतलब ऐसी स्थिति से नहीं है, जहां भारत खुद को पूरी दुनिया से अलग-थलग कर ले और अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा से भी बचने लगे। इसके बजाय आत्मनिर्भरता का मतलब देश के हित के लिहाज से अहम क्षेत्रों की पहचान कर उनमें निवेश करना है, ताकि सबसे नाजुक दौर में भी किसी और पर हमारी निर्भरता कम से कम हो।

आइए, हम सब मिलकर भारत को आत्मनिर्भर, बेहतर और ऊर्जावान बनाने के लिए काम करें, जिससे हमारी समृद्ध विरासत का और आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। ■

संदर्भ

1. चैप्टर 8 आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 उपलब्ध है - https://www.indiabudget.gov.in/budget2019-20/economicsurvey/doc/vol1chapter/echap08_vol1.pdf